

विषय: नगर पंचायत, महुआजाबरा (ऊधमसिंह नगर) हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

देहरादून : दिनांक 20 मार्च, 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 342/V-श.वि.-06-249(सा.)/2005 दिनांक 20.2.2006 एवं शासनादेश संख्या 801/V-श.वि.-06-166(सा.)टी.सी./03 दिनांक 29.3.2006 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20.2.2006 द्वारा स्वीकृत रु. 91 लाख के साक्ष्य शासनादेश दिनांक 29.3.2006 द्वारा मात्र रु. 68.69 लाख की धनराशि आहरित करने के निर्देश जारी किए गये थे। उक्तानुसार अवशेष धनराशि रु. 22.31 लाख (रु. बाइस लाख इकत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अत्यंत एवं आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का आवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. टाईल सहकों के निर्माण हेतु शासनादेश सं-3173/V-श.वि-0-2006, दिनांक-30 अगस्त, 2006 जा वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु Third Party Quality Checking की व्यवस्था की जायेगी जिस हेतु संबंधित संस्थाओं से अनुबन्ध होने के उपरान्त आवश्यक निर्देश प्रथम से निर्गत किये जायेंगे।
6. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगमन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विविधियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
7. कार्य पर चलना हो व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नाम है। स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विश्लेषणों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निष्पत्ति अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगमनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेंसी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णकाल उल्लेखनीय होंगे।

क्रमशः....

- 3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाधीनक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहयोग-03-नगरों का समीकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहयक अनुदान/अंशदान/राज सहयोग' के नाम से जाला जायेगा।
22. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगमन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
21. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
20. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयुक्त प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
19. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये। उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
18. विस्तृत आगमन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होना एवं कार्य करने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूमिगत के साथ आवश्यक करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकता अनुसार ही कार्य किये जायेंगे।
17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
16. आगमन में उल्लिखित दरों का विवरण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें डिजिटल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होना। तदोपरान्त ही आगमन की स्वीकृति मान्य होगी।
15. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुक्रम करायें जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अर्थात् धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
14. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगमन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
13. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, काटदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, गारंज करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा विले पोषण के शीत के विवरण के साथ एक साइडबाईड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
12. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवगुणित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
11. निर्माण एजेंसी के घयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. स्वीकृत कार्य करते समय वित्तीय दस्तावेज़िका, बजट मैनुअल, स्टैंडर परचेज रूलस एवं मितव्ययता सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगमन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य करने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अध्यासकीय संख्या : 2266/XXVII(2)/2007 दिनांक-23 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेंद्र सिन्हा)

सचिव।

संख्या 517 (1)/V/2007 तददिनांक 28/3/07

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रश्न), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अध्यक्ष/अधिकांशी अधिकारी, नगर पंचायत, महुवाडावरा (ऊधमसिंह नगर)।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आशा से,

(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।